वृद्धि-ध्रुव सिद्धान्त
Growth-Pole Theory

पाठ-संरचना (Lesson Structures)

3.0 उद्देश्य (Objective)

3.1 परिचय (Introductions)

3.2 वृद्धि-ध्रुव की संकल्पना (Concept of Growth-Pole)

3.3 भारतीय संदर्भ (Indian Context)

3.4 आलोचना (Criticism)

3.5 सारांश (Summing Up)

3.6 मॉडल प्रश्न (Model Questions)

3.8 संदर्भ पुस्तकें (Reference Books)

3.0 उद्देश्य (Objective)

प्रस्तुत अध्याय के द्वारा विद्यार्थियों को विकास/वृद्धि ध्रुव (Growth Pole) की मूल संकल्पना की जानकारी प्राप्त होगी। साथ ही इस अध्याय में ही भारत में इसकी महत्ता, उपयोगिता एवं व्यावहारिकता पर विस्तृत जानकारी प्राप्त होगी। अत: अध्याय के अध्ययन के बाद विद्यार्थी इस संकल्पना के सैद्धान्तिक (Theoritical) एवं व्यावहारिक (Applied) पक्षों से भली-भाँति अवगत होंगे।

3.1 परिचय (Introduction)

किसी देश की आर्थिक संवृद्धि और उसके विकास में उसके संसाधनों का कुशल और उपयुक्त दोहन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही संसाधनों के वितरण में भौगोलिक विविधता भी हो सकती है। इसी प्रकार किसी देश में वृद्धि (Growth) और विकास (Development) के दृष्टिकोण से विषमता भी विद्यमान हो सकती है। विकसित एवं विकासशील देशों में आर्थिक विषमता कम करने, तेज आर्थिक विकास करने तथा संसाधनों के यशोचित दोहन के मद्देनजर नियोजन की उपयोगिता बीसवीं सदी के पूर्वार्द्ध में महत्वपूर्ण बनी। प्रादेशिक विकास को ध्यान में रखकर विभिन्न अर्थशास्त्रियों एवं भूगोलवेत्ताओं द्वारा अनेक विचार प्रस्तुत किए गए जिन्हें बाद में 'प्रादेशिक विकास मॉडल' (Regional Development Model) के नाम से जाना जाता है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण 'मॉडल' निम्नलिखित हैं :-

(i) निर्यात आधारित मॉडल (Export Based Model): जिसका प्रतिपादन डगलस सी० नॉर्थ ने किया

(ii) 'आगम-निर्गत मॉडल' (Input-Output Model) जिसे लीयोन्टीफ (Leonteef) द्वारा प्रस्तुत किया गया।

(iii) वृद्धि ध्रुव मॉडल (Growth Pole Model) जिसका प्रतिपादन पेरोक्स (Perrourse) और बाउछेविले (Boudeville) द्वारा किया गया।

लेकिन आप सभी के पाठ्यक्रम (Syllabus) में केवल पेरोक्स (Perroux) के वृद्धि ध्रुव मॉडल (Growth Pole Model) का ही अध्ययन करना है। पेराक्स (Perroux) के वृद्धि ध्रुव मॉडल को जानने से पहले आइए हमलोग यह जानें कि विकास (Development) विकास केन्द्र (Growth Centre) और विकास/वृद्धि ध्रुव (Growth Pole) क्या है?

विकास (Development) : पहले की तुलना में अधिक वृद्धि, विस्तार या उत्थान की क्रिया या दशा। यह प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आदि विभिन्न प्रकार का हो सकता है।

विकास केन्द्र (Growth Centre) : किसी प्रदेश में स्थित ऐसे केन्द्र या अधिवास जिनमें अपने चारों ओर के क्षेत्रों के विकास करने की सामर्थ्य होती है। प्रादेशिक नियोजन के उद्देश्य से विकास केन्द्र के रूप में ऐसे सेवा केन्द्रों का चयन किया जाता है जिनके प्रभाव से उनके चारों ओर के अविकसित क्षेत्र भी विकसित होने लगते हैं।

विकास ध्रुव (Growth Pole) : किसी प्रदेश का वृहत्तम विकास केन्द्र जिसके प्रभाव से उसके अन्य विकास केन्द्रों का विकास होता है जिनसे अन्त में सम्पूर्ण प्रदेश के विकास को गति एवं दिशा मिलती है। वास्तव में यह प्रदेश के विकास का पुंज होता है जहाँ से विकास की लहरें पूरे प्रदेश में पहुँचती हैं।

3.2 वृद्धि ध्रुव की संकल्पना (Concept of Growth Pole)

फ्रांसीसी अर्थशास्त्री पेराक्स (Francois Perroux) ने 1955 ई० में वृद्धि-ध्रुव सिद्धांत (Theory of Growth Pole) का प्रतिपादन किया। पेराक्स मूलत: आर्थिक विकास की परिघटना और उस परिघटना के साथ होनेवाले ढाँचागत परिवर्तन की प्रक्रिया से सम्बन्धित रहे हैं। अपने वृद्धि-ध्रुव सिद्धांत में उन्होंने यह बताने की कोशिश की है कि कैसे संतुलित वृद्धि की स्थैतिक अवधारण से आर्थिक वृद्धि की आधुनिक प्रक्रिया विचलित या प्रभावित होती है।

पेरॉक्स (Perroux) के अनुसार- " Growth does not appear every where and all at once, it appears at points or development poles with variable intensities; it spreads along diverse channel and with varying terminal effects to the whole of the economy."

वृद्धि-ध्रुव का यह सिद्धान्त आर्थिक क्षेत्र के विचार से सम्बन्धित है, जिससे अपकेन्द्रीय (Centrifugal Forces) शक्तियाँ बाहर की ओर फैलती हैं तथा जिसकी ओर अभिकेन्द्रीय शक्तियाँ (Contripetal Forces) आकर्षित होमी है। प्रत्येक केन्द्र आकर्षण (Attraction) एवं प्रक्षेपण (Repulsion) केन्द्र के रूप में अपनी निजी सेवा रखता है, जो अन्य केन्द्रों के क्षेत्रों से सम्बन्धित होती हैं। इसे भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने का श्रेय बाउडेविले (Boudeville) को हैं जिन्होंने इसकी व्याख्या 1966 में प्रस्तुत की। ब्राउडेविले (Boudeville) के साथ ही वृद्धि-ध्रुव सिद्धांत भौगोलिक एवं प्रादेशिक (Regional) अहमियत वाला सिद्धांत बन गया। बाउडविले (Boudeville) ने प्रादेशिक वृद्धि-ध्रुव को इस तरह परिभाषित किया है- " A set of expanding industries located in an urban area and including further development of economic activity throughout its zone of influence," स्थल जहाँ यह प्रसार (Expanding) या उछाल या प्रक्षेपण (Propulsive) या प्रधान उद्योग (Dominat Industry) अवस्थित होता है, प्रदेश का ध्रुव (Pole) कहलाता है। यहाँ समूहन (Agglomeration) की

प्रवृति होती है। ऐसी प्रवृति बाहरी अर्थव्यवस्था के चलते पैदा होती है, जिसके परिणामस्वरूप ध्रुव के चारों ओर आर्थिक क्रियाकलापों का ध्रुवीकरण होता है। वृद्धि-ध्रुव के रूप में एक उद्योग या उद्योगों का समूह हो सकता है।

पेरॉक्स (Perroux) के वृद्धि-ध्रुव सिद्धान्त पर विभिन्न देशों के विद्वानों ने कार्य किये हैं। बाउडविले ने ब्राजील के मिनासगिरास राज्य के इस्पात उद्योग का अध्ययन कर उसे वृद्धि-ध्रुव के रूप में पाया। पेरिस के प्रादेशिक अर्थव्यवस्था को भी वृद्धि-ध्रुव माना गया है, क्योंकि पेरिस शहर के अध्ययन में यह पाया गया है कि ध्रुवीकरण (Polarization) का प्रभाव नजदीकी भौगोलिक क्षेत्रों के चारों तरफ हमेशा सकारात्मक नहीं रहा है। पेरिस शहर का आकर्षण इतना अधिक है कि उस शहर के बाहर के प्रदेशों में आर्थिक विकास को बल देना काफी कठिन है। परिणामस्वरूप फ्रांस के नियोजन साहित्य (Loterature) में इस प्रक्रिया को "Paris and the French Desert " कहा गया है।

संयुक्त राज्य अमेरिका में वृद्धि-ध्रुव की संकल्पना को प्रायः भौगोलिक अवस्थिति (Geographical Location) के रूप में देखा जाता है, जिसे वृद्धि-केन्द्र (Growth Centres) कहा जाता है। ये वृद्धि-केन्द्र समूहन (Agglomeration) की संकल्पना से सम्बन्धित है। अमेरिका में वृद्धि-केन्द्र पर किया गया काम कई मायनों में पेरॉक्स (Perroux) और फ्रांस के वृद्धि ध्रुव सिद्धान्त से काफी अलग है। अल्बर्ट हर्शमान (Albert Hirschman) ने वृद्धि-ध्रुव का निकटवर्ती प्रदेशों में नकारात्मक प्रभाव के लिए Trickling down शब्दों का प्रयोग किया है। स्वीडिश अर्थशास्त्री गुन्नार मिरडल (G. Myrdall) ने इन दोनों शब्दों के लिए क्रमशः Backwash and Spread शब्दों का प्रयोग किया है। अमेरिकी अर्थशास्त्री John R. Friedman ने इस सन्दर्भ में एक अलग ही विचार प्रस्तुत कर इसे केन्द्र (Centre) और बाहरी क्षेत्र (Periphery) के बीच का सम्बन्ध कहा। Friedman का यह विचार वेनेजुएला के तटीय प्रदेशों के बाद विकसित हुआ। आर० पी० मिश्रा (R.P. Mishra) द्वारा भारत के संदर्भ में वृद्धि-नाभि का चारसोपानी अनुक्रम (Four Tier Hieraricy) प्रस्तुत किया गया। (प्रकासा राव और सुन्दरम के साथ मिलकर), Regional Development Planning in India, 1974 जिसे 1974 में पाँचसोपानी अनुक्रम में संशोधित किया गया। इस अनुक्रम का आधार प्रदेशों और जनसंख्या का आकार था। इनके द्वारा प्रस्तावित वृद्धि नाभि के 'पाँच सोपानी अनुक्रम' (Five Tier Hierarchy) निम्न प्रकार है:-

1. **स्थानीय स्तर (Local Levlel) :** पर 'केन्द्रीय ग्राम' को रखा गया है जो लगभग 6 ग्रामों से बना 6000 की जनसंख्या वाला निम्नतर प्रादेशिक इकाई होगा। इसे एक नियोजित ग्रामीण बस्ती मानी जाती है जो विपणन, मनोरंजनात्मक, सामाजिक सेवाओं, सहकारी, प्राथमिक स्कूल इत्यादि गतिविधियों में शामिल होगा।

2. **व्यष्टि प्रादेशिक स्तर (Micro Regional Level)** पर 'सेवा केन्द्रों' (Service Centres) को रखा गया है जिसकी जनसंख्या का आकार लगभग 30,000 माना गया है (इसमें सेवा केन्द्र की अपनी जनसंख्या 5000 को नहीं जोड़ा गया है)। इनकी आर्थिक गतिविधियाँ पंसारी की दुकान, जनरल स्टोर, सामान्य मरम्मत सुविधाएँ, सिलाई, हजामत, होटल, सामुदायिक भवन, प्राथमिक एवं उच्च विद्यालय इत्यादि होगी।

3. **उप-प्रादेशिक स्तर (Sub-Regional Level)** पर 'वृद्धि बिन्दुओं' (Growth Points) को रखा गया जिसका जनसांख्यिक आकार लगभग 150,000 माना गया। इसकी अवधारणा नगर बाजार (Market Town) के समकक्ष हैं जिसे उप-प्रादेशिक स्तर पर प्रणोदी (Propulirive) और नवीन परिवर्तन लानेवाले केन्द्रों के रूप में देखा गया है। इनकी मूल आर्थिक गतिविधि कृषिगत उद्योग होगी जैसे कृषिगत उतपादों

के उत्पादन रख-रखाव से लेकर उनके प्रसंस्करण (Processing) इत्यादि तक।

4. **प्रादेशिक स्तर (Regional Level)** पर 'वृद्धि-केन्द्रों' (Growth Centres) को रखा गया जिसकी जनसंख्या का आकार लगभग 1,200,000 माना गया है। ऐसे केन्द्रों की अपनी जनसंख्या 50,000 से 500,000 तक माना गया है। वृद्धि बिन्दुओं के विपरीत इनकी मूल गतिविधि द्वितीयक (उद्योग) क्षेत्र से सम्बन्ध होगी।

5. **राष्ट्रीय स्तर (National Level)** पर 'वृद्धि ध्रुव' (Growth Poles) को रखा गया है, जिसका जनसांख्यिक आकार 20,000,000 माना गया है। वृद्धि ध्रुवों की अपनी जनसंख्या 500,000 से 2,500,000 मानी गयी है। इन्हें द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ क्षेत्रकों (Sectors) के उन उच्च-स्तरीय विशेषीकृत गतिविधियों में संलग्न बताया गया है जिनका सम्पादन निचले स्तर पर संभव नहीं हैं। साथ ही इन्हें समष्टि स्तर (Macro Level) पर 'हृदय (Heart) की तरह कार्य करता माना गया है।

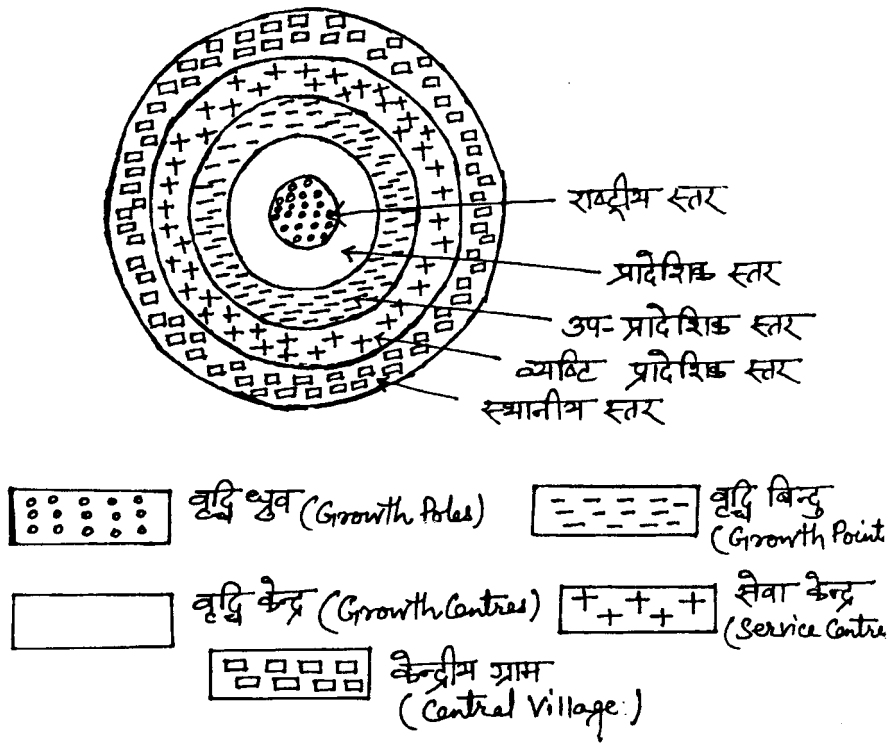

चित्र 1.1: आर० पी० मिश्रा, प्रकासा राव एवं सुन्दरम द्वारा प्रस्तावित (1974) 'वृद्धि नाभि' मॉडल

वृद्धि ध्रुव सिद्धान्त का यह संशोधित प्रारूप विकासशील और अल्पविकसित देशों के नियोजित विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान माना गया है। ग्राम्य एवं नगर दोनों प्रकार के प्रादेशिक नियोजनाओं को समेकित करते हुए प्रस्तुत किया गया। यह वृद्धि ध्रुव मॉडल अपने आप में एक 'पूर्ण' (Complete) रणनीति थी जिसमें आनेवाले दशकों के अन्यान्य सामाजिक-आर्थिक समस्याओं के निदान की उच्च स्तरीय प्रयास थी, जैसे:-

(i) कृषि, उद्योग एवं सेवा तीनों ही का समेकित और परस्पर विकास।

(ii) ग्रामीण एवं शहरी बेरोजगारी की समस्या का निदान

(iii) ग्राम्य-शहर प्रकासन से नगरों को भीड़-भाड़ से बचाने की युक्ति

(iv) नियोजन में पर्यावरण के प्रति सचेतता का पुट

(v) मनोरंजन, सृजनात्मकता, संवेदनशीलता तथा सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति समग्रता, इत्यादि।

3.3 भारतीय सन्दर्भ (Indian Context)

भारतीय नियोजन प्रक्रिया (राष्ट्रीय या प्रादेशिक) में कहीं-कहीं 'वृद्धि ध्रुव' (Growth Pole) के अतिरिक्त इस प्रकार के किसी मॉडल या सिद्धांत के आधिकारिक (Official) परिपालन का संकेत नहीं मिलता फिर भी तत सम्बन्धी अनेक सन्दर्भो तथा उदाहरणों को स्पष्ट देखा जा सकता है:-

(i) भारत की सभी बहुउद्देशीय परियोजनाएँ (दामोदर घाटी निगम, 1948 से लेकर अब तक) इस मॉडल पर आधारित ग्राम्य स्तर के प्रादेशिक नियोजन हैं जो अन्ततः राष्ट्रीय नियोजन के अंग है।

(ii) राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश (NCT) सहित दर्जनों शहरों के 'मास्टर प्लान' इस मॉडल पर आधारित नगरीय स्तर के प्रादेशिक नियोजन हैं जो राष्ट्रीय के अंग हैं।

(iii) विशेषज्ञों द्वारा भारत के सभी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को वृद्धि ध्रुव का उदाहरण माना जाता है (देश के अपेक्षाकृत पिछड़े क्षेत्रों में इन्हें 'प्रणोदी' (Propulsive) उद्योगों के रूप में स्थापित किया गया था जो नीति वर्ष 1956 से अबतक लगभग अपरिवर्तित रही है)।

(iv) भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में वृद्धि ध्रुव सिद्धांत से प्रेरित कई अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण भी दिखते है, जैसे निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (EPZs) निर्यातोन्मुख इकाइयाँ (EQUs) वर्तमान का विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZs); औद्योगिक क्षेत्र (Industrial Area), औद्योगिक संकुल (Industrial Complese) इत्यादि।

(v) व्यष्टि (Micro) स्तर (Level) से प्रारम्भ करके समष्टि (Macro) जैसे:- राष्ट्रीय नियोजन की हाल की एक बहुचर्चित योजना 'पुरा' (Pura) है जिसे वर्ष 2002 में ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं की पहुँच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रारम्भ किया गया।

3.4 आलोचना (Criticism)

वृद्धि ध्रुव सिद्धान्त के जहाँ एक तरफ विश्व के अनेक देशों ने अपनाया गया, वहीं दूसरी तरफ इस सिद्धांत को अनेक जटिल विषयपरक एवं अनुत्तरित आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। इस सिद्धांत की मुख्य आलोचनाएँ निम्न प्रकार से देखी जा सकती है:-

(i) कौन-सा उद्योग 'प्रणोदी' (Propulsive) है न सिर्फ इसका चयन कठिन है, बल्कि इसकी कोई वस्तुपूरक (Objective) विधि भी नहीं है।

(ii) किस प्रदेश/क्षेत्र के लिए कौन-सा प्रणोदी उद्योग उपयुक्त होगा यह चयन करना कठिन है।

(iii) प्रणोदी एवं उद्योगों के लिए आधारभूत संरचनाओं का विकास एक कठिन, दीर्घावधिक और उच्च निवेश वाला कार्य है।

(iv) वृद्धि ध्रुव की तरफ उधमियों (Entrepreneurs) का आयात एक जटिल एवं कठिन कार्य है।

(v) आलोचको के अनुसार वृद्धि ध्रुव के वृद्धिकारी प्रभाव न सिर्फ इन ध्रुवों के काफी निकट तक

सीमित रहे (वास्तविक उदाहरणों से पता चलता है) बल्कि परिधि की तरफ जाते हुए तेजी से क्षीण भी होते रहे।

(vi) कुछ आलोचकों का मानना है कि विश्व के देशों द्वारा इस मॉडल को बिना 'वस्तुपूरक जाँच' किए बिना ही अपनी नियोजन प्रक्रियाओं में एक 'धार्मिक विश्वास' (Religious Belief) के रूप में अपनाने का 'फैशन-सा चल पड़ा।

जहाँ एक ओर आलोचकों द्वारा इस मॉडल की काफी तर्कसंगत और कठोर आलोचनाएं प्रस्तुत की गयीं, वही विश्व की अनेक सरकारों, विशेषज्ञों एवं नीति नियामकों की यह मान्यता भी मजबूत बनी रही कि वृद्धि ध्रुव ने केन्द्र एक बड़े प्रदेश/क्षेत्र में वृद्धि और विकास को गति प्रदान की। यही कारण है कि विश्व के अनेक देशों द्वारा इस अवधारणा को अपनी नियोजन की नीतियों में बढ़ा-चढ़ाकर जगह दिया गया।

3.5 सारांश (Summing-up)

किसी भी देश में वृद्धि (Growth) और विकास (Development) के दृष्टिकोण से विषमता भी विद्यमान हो सकती है। विकसित और विकासशील देशों में आर्थिक विषमता कम करने, तेज आर्थिक विकास करने तथा संसाधनों के न्योचित दोहन को ध्यान में रखकर नियोजन की उपयोगिता बीसवीं सदी के पूर्वार्द्ध में महत्वपूर्ण बनी। प्रादेशिक विकास को ध्यान में रखकर विभिन्न अर्थशास्त्रियों एवं भूगोलक्ताओं द्वारा अनेक विचार दिए गए। जिसमें फ्रांसीसी अर्थशास्त्री पेरॉक्स (Francois Perroiux) के द्वारा 1955 में वृद्धि ध्रुव सिद्धांत (Growth Pole Theory) प्रतिपादित हुआ।

पेरॉक्स (Perroux) के अनुसार- " Growth does not appear every where and all at once, it appears at points of development poles with variable intenisities; it spread along diverse channel and with varying terminal effects to the whole of the economy."

वृद्धि-ध्रुव का यह सिद्धांत आर्थिक क्षेत्र के विचार से सम्बन्धित है, जिससे अपकेन्द्रीय (Centrifugal Forces) शक्तियाँ बाहर की ओर फैलती हैं तथा जिसकी ओर अभिकेन्द्रीय शक्तियाँ (Centripetal Forces) आकर्षित होती हैं। प्रत्येक केन्द्र आकर्षण (Attraction) एवं प्रक्षेपण (Repulsion) केन्द्र के क्षेत्रों से सम्बन्धित होती है। इसे भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने का श्रेय बाउडेविले (Boudeville) को है जिसकी व्याख्या उन्होंने 1966 में की। वाउडविले (Boudeville) ने वृद्धि-ध्रुव को इस तरह परिभाषित किया है- "A set of expanding industries located in an urban area and including further development of economic activity through-out its zone of influence."

स्थल जहाँ यह प्रसार (Expanding) या उछाल या प्रक्षेपण (Propulsive) या प्रधान उद्योग (Dominant Industry) अवस्थित होता है, प्रदेश का ध्रुव (Pole) कहलाता है। यहाँ समूहन (Agglomeration) की प्रवृति होती है। ऐसी प्रवृति बाहरी अर्थव्यवस्था के चलते पैदा होती है, जिसके परिणास्वरूप ध्रुव के चारों ओर आर्थक क्रियाकलापों का ध्रुवीकरण होता है। वृद्धि-ध्रुव के रूप में एक उद्योग या उद्योगों का समूह (Group) हो सकता है।

पेरॉक्स (Perrouse) के वृद्धि-ध्रुव सिद्धांत पर विभिन्न देशों के विद्वानों ने कार्य किये हैं जिसमें अल्बर्ट हर्शमान (A. Hirschman) और भारत के आर० पी० मिश्रा (R.P. Mishra) के नाम शामिल हैं। पेरॉक्स ने आर० पी० मिश्रा (R.P. Mishra) द्वारा प्रस्तावित वृद्धि नाभि के 'पाँच सोपानी अनुक्रम' (Five Tier Hierarchy) में रखा:-

(i) स्थानीय स्तर (Local level)

(ii) व्यष्टि प्रादेशिक स्तर (Micro Regional level)

(iii) उप-प्रादेशिक स्तर (Sub-Regional level)

(iv) प्रादेशिक स्तर (Regional Level)

(v) राष्ट्रीय स्तर (National Level)

जहाँ तक वृद्धि-ध्रुव (Growth Pole) मॉडल का भारत के सन्दर्भ में उपयोगिता का प्रश्न है तो भारत की सभी बहुद्देशीय परियोजनाएँ इसी मॉडल पर आधारित ग्राम्य स्तर के प्रादेशिक नियोजन हैं जो अन्नत: राष्ट्रीय नियोजन के अंग हैं।

जहाँ एक तरफ विश्व के अनेक देशों की लोक नीति में वृद्धि ध्रुव मॉडल को अपनाया गया, वहीं दूसरी तरफ इस सिद्धांत को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा जो निम्न है:-

(i) कौन-सा उद्योग 'प्रणोदी' (Propulsive) है न सिर्फ इसका चयन कठिन है बल्कि इसकी कोई वस्तुपूरक (objective) विधि भी नहीं है।

(ii) किस प्रदेश / क्षेत्र के लिए कौन-सा प्रणोदी उद्योग उपयुक्त होगा यह चयन करना कठिन है।

(iii) कुछ आलोचकों का मानना है कि विश्व के देशों द्वारा इस मॉडल को बिना 'वस्तु पूरक जाँच' किए बिना ही अपनी नियोजन प्रक्रियाओं में एक 'धार्मिक विश्वास' (Religious Belief) के रूप में अपनाने का 'फैशन-सा' चल पड़ा।

जहाँ एक ओर आलोचकों द्वारा इस मॉडल की काफी आलोचनाएँ हुई, वहीं विश्व की अनेक सरकारें इस अवधारणा को अपनी नियोजन की नीतियों में बढ़ा-चढ़ाकर स्थान दिया है।

3.6 मॉडल प्रश्न (Model Questions)

1. वृद्धि केन्द्र क्या है? वृद्धि ध्रुव (Growth Pole) की संकल्पना को स्पष्ट करें।
2. आर० पी० मिश्रा (R.P. Mishra) द्वारा प्रस्तावित भारत के वृद्धि नाभि के सोपानी अनुक्रम की व्याख्या करें।
3. भारतीय नियोजन में वृद्धि-केन्द्र एवं वृद्धि ध्रुव संकल्पना की उपयोगिता पर प्रकाश डालें।

3.7 संदर्भ पुस्तकें (Reference Books)

1. M.Chand & V.K. Puri : Regional Planning in India
2. R.P. Mishra : Regional Planning in India
3. Chandana : Regional Development & Plannig
4. नन्देश्वर शर्मा : प्रादेशिक नियोजन
5. श्रीवास्तव, शर्मा एवं चौहान : प्रादेशिक नियोजन और सन्तुलित विकास।
6. माजिद हुसैन एवं रमेश सिंह : भौगोलिक मॉडल्स

●●●

इकाई-5

क्रिस्टालर की केन्द्रीय स्थल समस्याएँ (Christaller's Central Place Theory)

पाठ-4

पाठ-संरचना (Lesson Structures)

4.0 उद्देश्य (Objective)

4.1 परिचय (Introductions)

4.2 क्रिस्टालर का केन्द्रीय स्थल सिद्धान्त (Central Place Theorty of Christaller)

4.3 केन्द्रीय स्थल सिद्धान्त की मान्यताएँ (Postulates of Central Place Theory)

4.4 क्रिस्टालर का स्थिर 'क' पदानुक्रम (Christaller's Fixed 'K' Hierarchy)

4.5 भारत में केन्द्रीय स्थान (Central Places in India)

4.6 आलोचना (Criticism)

4.7 सारांश (Summing up)

4.8 मॉडल प्रश्न (Model Questions)

4.9 संदर्भ पुस्तकें (Reference Books)

4.0 उद्देश्य (Objective)

इस अध्याय का उद्देश्य विद्यार्थियों को 'केन्द्रीय स्थान सिद्धान्त' जो कि वॉल्टर क्रिस्टॉलर द्वारा प्रतिपादित है, के बारे में जानकारी देनी है और भारत में इसके व्यवहारिक प्रासंगिकता को समझाना है।

4.1 परिचय (Introduction)

जर्मन अथशास्त्री वाल्टर क्रिस्टॉलर (Watter Christaller) ने 1933 में जर्मन भाषा में अंग्रेजी अनुवाद 1966) केन्द्रीय स्थान सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। केन्द्रीय स्थान सिद्धान्त (Central Place Theorty) उस प्रक्रिया से सम्बन्धित है, जिससे अधिवास (Settlement) उत्पन्न और विकसित होते हैं। क्रिस्टॉलर ने अपने सिद्धान्त का आधार बवेरिया (दक्षिण जर्मनी) से प्राप्त आँकड़ों को बनया।

क्रिस्टॉलर का मानना था कि जितना बड़ा नगर होगा उसका उतना बड़ा सेवित क्षेत्र होगा। किसी भी प्रदेश या देश में छोटे पुरवे (जो कि कुछ साधारण से कार्य जैसे सीमित समीपवर्ती क्षेत्र के लिए सीमित सेवा उपलब्ध करता हो) से लेकर वृहद् नगर (जो अधिक संलिष्ट सेवायें जैसे शोक व्यापार, बैंक सेवा, विशिष्टीकृत फुटकर व्यापार आदि एक वृहद समीपवर्ती क्षेत्र के लिए उपलब्ध कराता हो) तक सम्मिलित होंगे। ऐसे सेवा कार्य जो किसी केन्द्र द्वारा अपने समीपवर्त्ती क्षेत्र को विशुद्ध रूप से प्रदान कराये जाते हैं, उन कार्यों को क्रिस्टॉलर

'केन्द्रीय कार्यों (Central Functions) तथा केन्द्रीय कार्यों को सम्पन्न करनेवाले अधिवासों को 'केन्द्रीय स्थान' (Central Place) की संज्ञा दी। (''Services performed purely for a Surrounding area are termed 'Central functions* by Christaller, and the settements performing them 'Central Place ..... R.E. Dickinson)

4.2 क्रिस्टॉलर का 'केन्द्रीय स्थान सिद्धान्त (Central Place Them of Christaller)

'वाल्टर क्रिस्टॉलर महोदय का सिद्धान्त दो आधारभूत अवधारणाओं पर आधारित हैं :-

(अ) केन्द्रीकरण का सिद्धान्त (Centralization's Theory).

(ब) पदानुक्रम का सिद्धान्त (Hieraricy's Theory)

(अ) केन्द्रीकरण का सिद्धान्त :- ब्रह्माण्ड के सारे पदार्थ, चाहे जीव हो या निर्जीव, उनका एक कारे या केन्द्रीय बिन्दु (Central Point) होता है और उनकी परिधि होती है। जैसे :- सूर्य, सौरमण्डल के केन्द्र में स्थित है, नयुट्रान, परमाणु केन्द्र में स्थत है। ठीक इसी तरह प्रदेशों के भी केन्द्रीय बिन्दु और परिधिय क्षेत्र होते हैं। प्रदेशों के भी केन्द्रीय बिन्दु और परिधिय क्षेत्र होते हैं। गाँव में केन्द्रीय बिन्दु मंदिर, मस्जिद, चर्च या चौपाल होता है। आगे बड़े अधिवासों के चारों और छोटे-छोटे अधिवास संगठित हो जाते हैं, जो अपने चारों ओर के अधिवासों को केन्द्रीय बिन्दु के रूप में सेवा देते हैं। दूसरे शब्दों में छोटे कस्बे बहुत से गाँवों और पुरवों (Hamlets) को केन्द्रीय बिन्दु के रूप में सेवा देते हैं। यह जरूरी नहीं है कि यह केन्द्रिय बिन्दु अधिवासों का ज्यामितिय केन्द्र ही हो। इस तरह केन्द्रीकरण एक ज्यामितिय अवधारणा नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी अवधारणा है जो केन्द्रीय अधिवास ओर उसके परिधिय (समीपवर्ती) अधिवासों से आपसी सम्बन्धों से जुड़ी है।

(ब) पदानुक्रम का सिद्धान्त :- अधिकांश तथ्यों एवं दृश्यों का एक पदानुक्रमिक संगठन होता है। इसीलिए, हर जगह प्रशासनिक पदानुक्रम तथा प्रत्येक संस्था में एक सहभागी पदानुक्रम व्यवस्था विद्यमान होती है। पदानुक्रम स्वयं को क्षेत्रीय क्षेणियों एवं स्थानों के रूप में अभिव्यक्त करता है, जैसे - राज्य, जिला एवं तहसील मिलकर एक प्रशासनिक-क्षेत्रीय पदानुक्रम की रचना करते हैं, जिनको स्थान-पदानुक्रम में राज्य की राजधानी, जिला- मुख्यालय तथा तहसील मुख्यालय का सम्मान प्राप्त होता है। इस तरह केन्द्रीकरण सिद्धान्त और पदानुक्रम सिद्धान्त की सार्वभौमिक महत्ता है।

केन्द्रीय स्थान सिद्धान्त में छः (6) प्रधान संकल्पना विद्यमान हैं :-

(i) केन्द्रीय स्थान की संकल्पना (Central Place Concept),

(ii) पूरक क्षेत्र की संकल्पना (Complementary Place Concept),

(iii) केन्द्रीय वस्तुओं और सेवाओं की संकल्पना (Central Goods and Services concept),

(iv) वस्तुओं के परिसर की संकल्पना (Range of Goods),

(v) देहरी के संकल्पना (Threshold Concept),

(vi) केन्द्रीयता की संकल्पना (Nodality Concept/Focal Point),

(i) केन्द्रीय स्थान की संकल्पना (Central Place Concept) :-

केन्द्रीय स्थान एक ऐसा अधिवास होता है, जो इसके ऊपर निर्भर बहुत से अन्य अधिवासों को केन्द्रीय बिन्दु के रूप में सेवा प्रदान करता है।

(ii) पूरक क्षेत्र/सहायक क्षेत्र की संकल्पना (Complementary Area) :-

पूरक क्षेत्र केन्द्रीय स्थान के अनुलग्न (Adjacent) के रूप में है। सैद्धान्तिक अर्थ मे, यह कम और ज्यादा महत्त्व के छोटे-छोटे अधिवासों का संग्रह है। यह विस्तृत, दीर्घत्तर और ज्यादा महत्त्वपूर्ण केन्द्रीय स्थान हो सकता है।

(iii) केन्द्रीय वस्तुओं एवं सेवाओं की संकल्पना (Central Goods & Services Concept) :-

किसी केन्द्रीय स्थान द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं को उपलब्ध कराना ही उसका प्राथमिक कार्य है। केन्द्रीय स्थान आवश्यक रूप से तृतीयक क्रियायें ही सम्पन्न करता है। केन्द्रीय स्थान द्वारा उपलब्ध करायी जानेवाली वस्तुओं साधारण उपभोग (वस्त्र, फुटवियर, स्टेशनरी, इलेक्ट्रिकल सामान, किराना) से लेकर महंगे उपलकरण, वस्त्र और आभूषण इत्यादि कुछ भी हो सकती है। बड़े केन्द्रीय स्थान इन वस्तुओं के अतिरिक्त कुछ ऐसी वस्तुएँ भी उपलब्ध कराते हैं जो प्राय: उपयोग की होती है तथा साथ ही साथ जिनकी कीमत भी ज्यादा होती है। जैसे :- महँगे कपड़े, आभूषण, रेडियो, टेलिविजन सेट, मोटर बाइक, कार, ट्रैक्टर, उच्च शैक्षणिक संस्थान तथा महँगी चिकित्सा सुविधायें।

(iv) वस्तुओं के परिसर की संकल्पना (Range of Goods) :-

चूँकि वस्तुयें और सेवायें केन्द्रीय स्थानों पर ही उपलब्ध होती हैं, इसलिए पूरक क्षेत्रों (Complenaentary Areas) के उपभोक्ताओं को इन्हें प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय स्थान तक एक निश्चिम दूरी तक यात्रा करनी पड़ती है। प्राथमिक जरूरतों के लिए कोई व्यक्ति भले ही सामान्यत: 1 Km. से ज्यादा की यात्रा न करे, परन्तु विलासितापूर्ण वस्तुओं के लिए वह 100 Km. या अधिक दूरी तक यात्रा कर सकता है।

(v) देहरी की संकल्पना (Threshold's Concept) :-

किसी दुकान द्वारा किसी वस्तु को उपलब्ध कराने के लिए यह जरूरी है कि उस वस्तु के उपभोक्ताओं की संख्या इतनी हो कि सेवा (Service) प्रदाता के लिए यह लाभदायक काम बना रहे। उपभोक्तओं (Customer) की यह न्यूनतम संख्या ही वस्तुओं एवं सेवाओं की देहरी (Threshold) होती है।

(vi) केन्द्रीयता की संकल्पना (Nodality/Focal Point Concept) :-

केन्द्रीय स्थान संकल्पना स्वयं में किसी केन्द्र के केन्द्रीय बिन्दु (Focal Point) के रूप में उसके महत्त्व को व्यक्त करती है। केन्द्रीय स्थान को मिलनेवाला यह महत्त्व वस्तुओं एवं सेवाओं की उपलब्धता, पूरक क्षेत्रों के आकार तथा केन्द्रीय स्थान को आनेवाले व्यक्तियों की संख्या द्वारा निर्मित (उत्पन्न) होता है।

4.3 केन्द्रीय स्थल सिद्धान्त की मान्यतायें (Postulates of Central Place though)

किस्टॉलर ने माना कि केन्द्रीय स्थान सिद्धान्त (Central Place Theory) तभी लागू होगा, जब निम्न भू-पारिस्थितिक और सामाजिक-सांस्कृतिक दशायें विद्यमान होंगी :-

(i) भूदृश्य एक समदैशिक (Isotropic) सतह हो (जहाँ जलवाय और धरातलीय एकरूपता)

(ii) संसाधनों के संदर्भ में अधिवासों का वितरण हो।

(iii) जनसंख्या और उनके आम-स्तर का वितरण लगभगसमान हो।

(iv) सभी लोग लगभग समान आम स्तर के हों।

(v) क्रेता और विक्रेता (दुकानदार) दोनों बुद्धिमान हो जो अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करते हों।

(vi) अधिवासों का सम्पूर्ण क्षेत्र पूर्णरूप से समरूप केन्द्रीय स्थानों द्वारा सेवा प्राप्त करता है। यहाँ पर क्षेत्र का कोई भी हिस्सा छटने नहीं पाता है और न ही किसी एक क्षेत्र को एक से अधिक केन्द्र सेवा प्रदान करते हैं। यह तभी संभव है जब केन्द्रीय स्थान षटभुजीय (Hexagonal) व्यवस्था में स्थित हों। यदि इनका वितरण वृत्ताकार व्यवस्था में होगा तो पूरक क्षेत्रों के बीच या तो खाली स्थान छूटेगा (जिसमें किसी भी केन्द्र से सेवा नहीं प्राप्त होगी) या पूरक क्षेत्र आपस में अध्यारोपित (Superimposed) होंगे और इस तरह उनके बीच निरर्शक प्रतिस्पर्धा जन्म होगी। भिन्न सामर्थ्य स्तर के अधिवासों के विभिन्न वेष्टित (Packing) प्रासयों को चित्र (4.1 & 4.2) में दिखाया गया है।

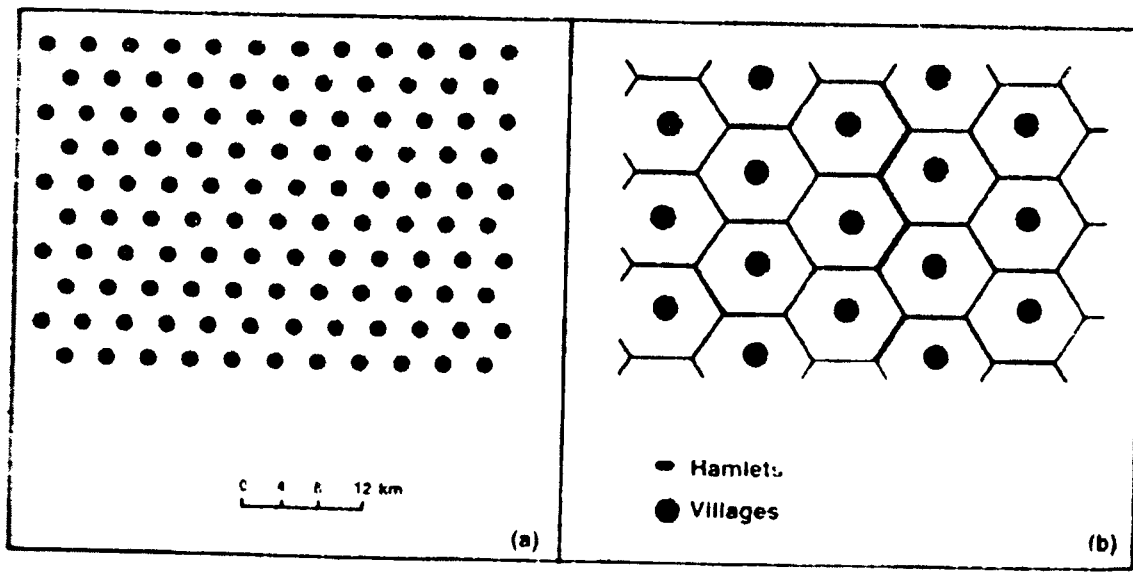

(After R. Knowles. et al. 2002 : 227)

चित्र 4.1 : मूल पुरवा (hamlet) की जाली (grid) तथा षटकोणीय सेवा क्षेत्रों का विकास
(a) समबाहु त्रिभुज (जाली) पर एक-दूसरे से 4 किमी. स्थित पुरवे;
(b) K = 3 अनुक्रम के आधार पर पुरवा तथा ग्राम सेवा क्षेत्रों का प्रतिरूप।

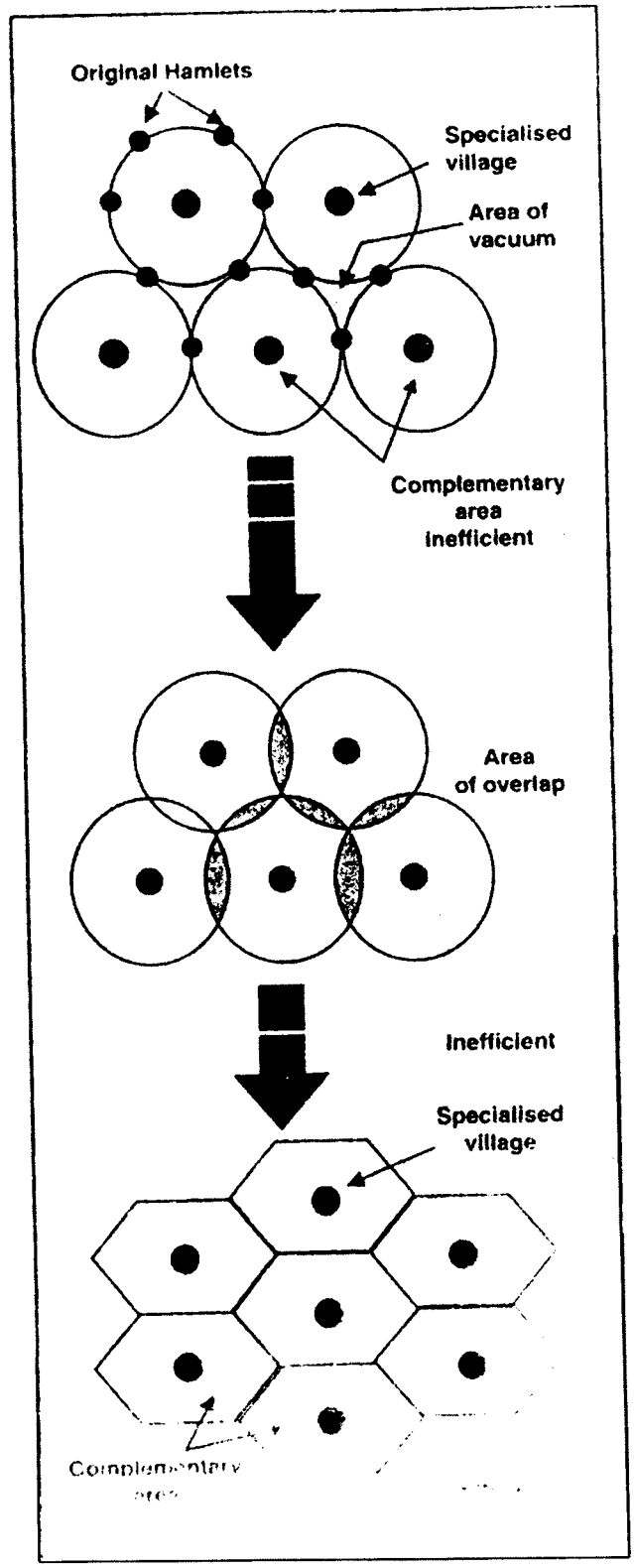

चित्र :- 4.2 विभिन्न दक्षता स्तरों वाले अधिवासों के वेष्टित प्रतिरूप

4.4 क्रिस्टालर का स्थिर 'क' पदानुक्रम (Christaller's Fixed K-Hierarchy)

क्रिस्टॉलर के अनुसार प्रत्येक सेवा क्षेत्र के षट्भुजीय (Hexagonal) आकृति में विकसित केन्द्रीय स्थानों की संख्या का अपने से अगले पदानुक्रम के केन्द्रीय स्थानों की संख्या से एक स्थिर गणितीय अनुपात होता है। यही स्थिर गणितीय अनुपात 'क' मूल्य ('K' value) कहा जाता है अर्थात् एक केन्द्रीय स्थान में जितनी बस्तियों की सेवा प्रदान की जाती है, उन बस्तियों की संख्या उस केन्द्रीय स्थान का 'क' मूल्य ('K' value) कहलाती है।

("The 'K' value is simply the number of statements which a central place is able to serve.")

क्रिस्टालर महोदय ने 'क' मूल्य की गणना निम्न तीन आधार पर की :-

(1) बाजार सिद्धान्त (Market Principle) K = 3

(2) परिवहन सिद्धान्त (Transport Principle) K = 4

(3) प्रशासनिक सिद्धान्त (Administrative Principle) K = 4

(1) बाजार सिद्धान्त (Market Principle) :- इस सिद्धान्त के आधार पर क्रिस्टालर महोदय ने बताया कि एक केन्द्रीय स्थान पर निर्भर छह सेवा केन्द्रों में कोई से दो सेवा केन्द्र बाजार के रूप में विकसित होने में सफल हो जाते हैं। अत: एक केन्द्रीय स्थान (बाजार केन्द्र) स्वयं की सेवा करने के साथ-साथ दो अन्य केन्द्रों की जनसंख्या की बाजार आवश्यकताओं की आपूर्ति करेगा चित्र 4.3 में।

इस प्रकार बाजार सिद्धान्त के आधार पर विकसित केन्द्रीय स्थान अपनेसे तीन गुनी जनसंख्या को सेवायें उपलब्ध करायेगा। अत: इस सिद्धान्त के आधार पर

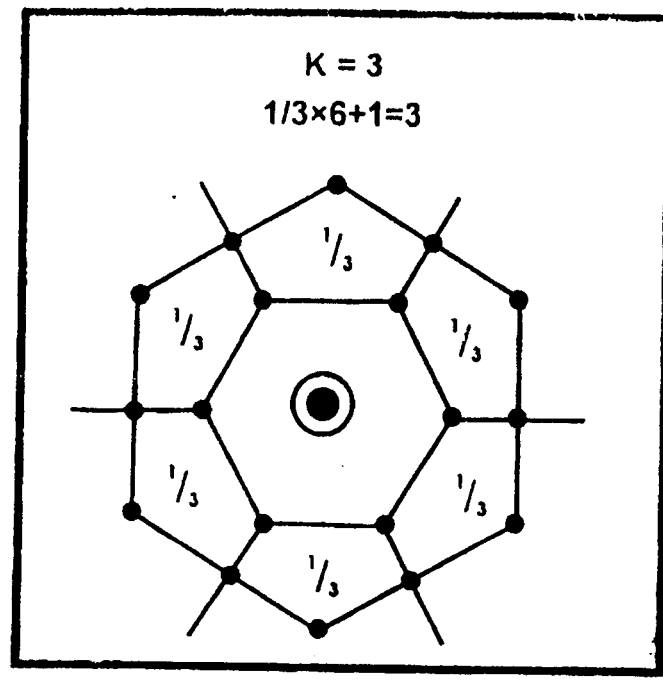

चित्र : 4.3 : 'क' मूल्य तथा षट्कोणीय व्यवस्था

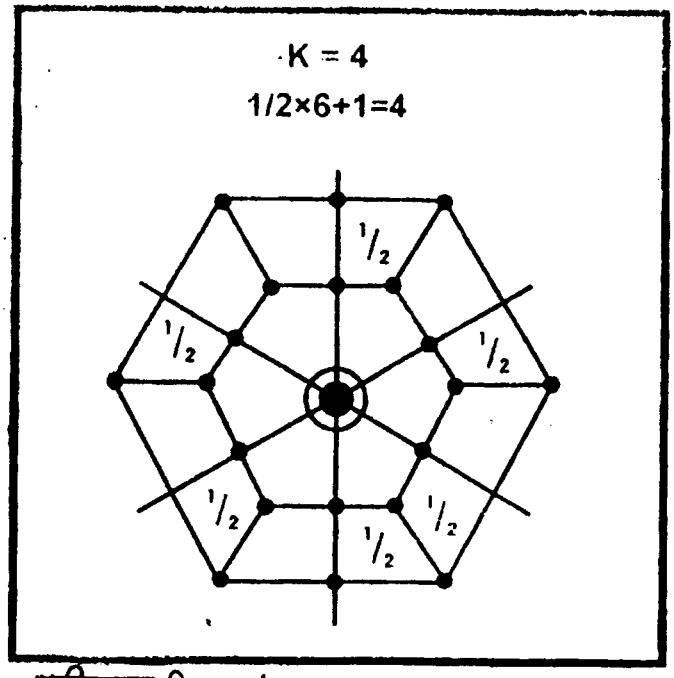

चित्र : 4.4 : 'क' मूल्य तथा षट्कोणीय व्यवस्था

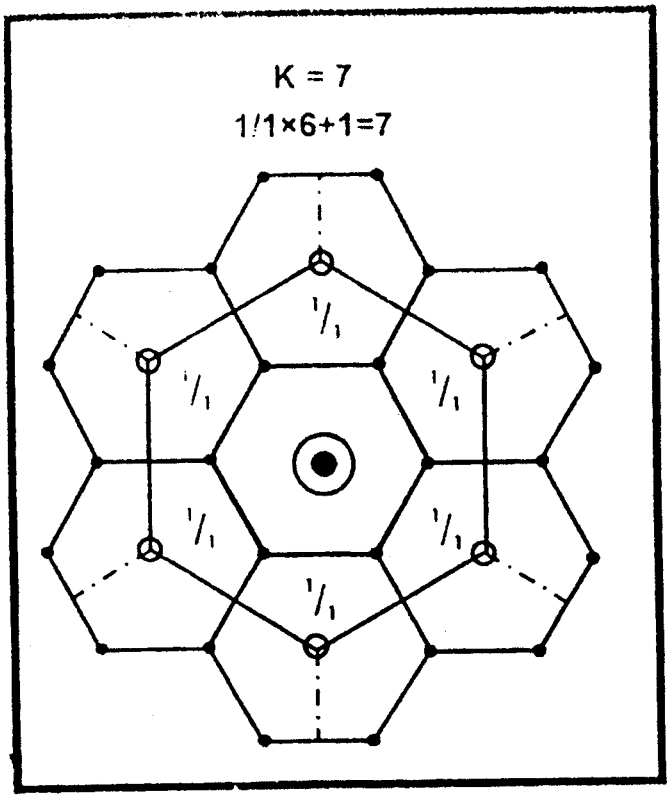

चित्र : 4.5 : 'क' मूल्य तथा षट्कोणीय व्यवस्था